Review meeting by Chief Minister Himachal Pradesh through NIC Video Conferencing with Deputy Commissioners

Date: 9-September-2008 **Time**: 3:30 PM to 5:15 PM
Sites: CM Office at Shimla and 12 Districts
Connectivity: MCU Shimla, Leased Line-10 Districts, ISDN to MCU at VC Delhi, 2 DAMA VSATs

<u>Participants</u>
CM Office

- Chief Minister Himachal Pradesh
- Principal Secretary (Revenue)
- Principal Secretary (CM, Excise & Taxation, IPR, AH)
- Secretary (Food & Civil Supplies)
- Secretary (CM, Information Technology)
- Secretary (RD & PR)
- SIO, NIC HP
- Director (RD &PR), Director (Food & Civil Supplies)

Districts

- All 12 Deputy Commissioners and Commissioner MC, Shimla
- District Revenue Officers, Civil Supplies Officers, PWD and IPH Officers

Prof Prem Kumar Dhumal, Chief Minister Himachal Pradesh, held a review meeting to assess the damage caused due to rains/ floods in the State, status of public distribution system and grievances redressal by holding a VC with all Deputy Commissioners of the State. The VC was conducted at a short notice and **all modes of communication were utilized by NIC State Centre and NIC Hqrs New Delhi to ensure that all 12 sites were connected**. The BSNL leased line was down in two districts Kinnaur and Lahaul & Spiti and disconnected between Chandigarh & New Delhi. Therefore, ISDN connectivity was used to connect to NIC Hqrs, New Delhi MCU and this MCU was used to connect to the two districts through DAMA VSATs.

VC with Lahaul & Spiti (Keylong) through ISDN between Shimla MCU and NIC Hqrs, New Delhi MCU and from there to Keylong through DAMA VSAT

A view of the VC in progress in Chief Minister's Conference Hall

Press Clippings (9th September 2008)

Punjab Kesari

बाढ़ से हिमाचल को 1541 करोड़ की क्षति

वीडियो कांफ्रेंस से मुख्यमंत्री ने लिया हालात का जायजा, आवश्यक निर्देश जारी

शिमला, 8 सितम्बर (ब्यूरो) : प्रदेश में व्यापक वर्षा के कारण फसलों एवं अधोसंरचना को 1541 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान है। यह जानकारी मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को यहां प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारी वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में खड़ी फसलों, सड़कों एवं भवनों को व्यापक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के कारण 1,41,572 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र तथा 12,988 हैक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि फसलों को लगभग 199.47 करोड़ रुपए और बागवानी क्षेत्र में 204.60 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सड़कों, पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं को भी भारी नुक्सान हुआ है और 180 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उपायुक्तों एवं विभिन्न विभागों को 106 करोड़ रुपए की राहत राशि आबंटित की है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 500 करोड़ रुपए की अंतरिम बाढ़ राहत प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि राहत एवं पुनर्वास कार्यों को और तेज किया जा सके। प्रो. धूमल ने कहा कि बरसात का मौसम अभी भी जारी है इसलिए इन अनुमानों के बढ़ने की संभावनाएं हैं क्योंकि अभी प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों से जिला एवं प्रदेश मुख्यालय पर क्षति का सही अनुमान प्राप्त किया जा रहा है। इसके बाद ही केंद्र सरकार को संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ताकि उचित धनराशि प्राप्त की जा सके। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जन शिकायत के निवारण को विशेष प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायतों पर (शेष पृष्ठ 2 कालम 3 पर)

शिमला : मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बात करके बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लेते हुए।

हरियाणा • उत्तराखंड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

बारिश में बहे 1541 करोड़ : धूमल

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से जाना जिलों का हाल

जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से 1541 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 500 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत मांगी है, ताकि राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेज किया जा सके। यह जानकारी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को जिला उपायुक्तों से बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान दी।

- केंद्र से मांगी पांच सौ करोड़ की अंतरिम राहत
- जन शिकायतों पर क्षेत्रीय अधिकारी ही करें कार्रवाई

उन्होंने कहा कि बारिश से 1 लाख 41 हजार 572 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र व 12 हजार 988 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। फसलों को करीब 199.47 करोड़ व बागवानी क्षेत्र में 204.60 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सड़कों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ है। 180 करोड़ की निजी संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावितों को राहत देने के लिए उपायुक्तों व विभिन्न विभागों को 106 करोड़ की राशि जारी की है। विधानसभा के मानसून सत्र में केंद्र से बाढ़ राहत सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी भी बारिश जारी है और जिला एवं प्रदेश मुख्यालय पर क्षति का सही अनुमान प्राप्त किया जा रहा है। इसके बाद ही केंद्र सरकार को संकलित रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जन शिकायत के निवारण को विशेष प्राथमिकता दें। प्रत्येक शिकायतों पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। प्रदेश भर में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

धूमल ने सीमावर्ती जिलों में विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि किन्नौर व स्पीति घाटी के लोगों को रोहतांग और कुंजम दर्रे से होते हुए रसोई गैस उपलब्ध करवाएं, क्योंकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग मालिंग नाला पर अवरुद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने को कहा। मादक वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान व शिक्षण संस्थानों के नजदीक सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आवंटित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए कहा।

Amar Ujaala

ंडीगढ़, मंगलवार, 9 सितम्बर, 2008

बताइए, आपके जिले में कितना हुआ नुकसान

उपायुक्तों ने कहा, लगभग 1514 करोड़ रुपये की हुई हानि

प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सभी जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जायजा लेते हुए।

शिमला। भारी बारिश के कारण प्रदेश में फसलों एवं अधोसंरचना को 1541 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है। बरसात जारी है और क्षति का अनुमान और बढ़ सकता है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से पांच सौ करोड़ रुपये की अंतरिम राहत का आग्रह किया है। केंद्र को भारी बारिश से हुए नुकसान की संकलित रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों से बरसात में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जन शिकायत निवारण को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को निर्धारित समय अवधि में खुला शौचमुक्त किया जाएगा। उपायुक्तों को जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के समुचित भंडारण को सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए गए।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग

बरसात जारी, अभी और बढ़ सकता है क्षति का अनुमान

केंद्र से पांच सौ करोड़ की अंतरिम बाढ़ राहत का आग्रह

उन्होंने कहा कि बारिश से खड़ी फसलों, सड़कों, भवनों को भारी क्षति हुई है। बारिश से 1 लाख 41 हजार 572 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र और 12,988 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। फसलों को लगभग 199.47 करोड़ रुपये और बागवानी को 204.60 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में सड़कों, पेयजल परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाओं को भारी क्षति हुई है। 180 करोड़ रुपये की निजी संपत्ति बारिश से क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने संसाधनों से लोगों को राहत प्रदान के लिए उपायुक्तों के माध्यम से 106 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी कर दी है। प्रदेश सरकार के आग्रह पर हाल ही में खत्म हुए मानसून सत्र में केंद्र से उदार बाढ़ राहत सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र से 500 करोड़ रुपये की अंतरिम बाढ़ राहत प्रदान करने का आग्रह किया है, ताकि पुनर्वास और राहत कार्यों को तेज किया जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों से जिला एवं प्रदेश मुख्यालय में क्षति का सही अनुमान प्राप्त किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार को संकलित रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि उचित धनराशि प्राप्त की जा सके। प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी श्रम शक्ति, एवं उपकरण राहत और परियोजनाओं के फिर बहाल करने में लगा दिए हैं। आम आदमी को दिक्कतों से दूर रखने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

उपायुक्तों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनशिकायत निवारण को विशेष प्राथमिकता दें। प्रत्येक शिकायतों पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही सहन नहीं की जाएगी। प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को कारगरता से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत एवं शिक्षण संस्थान में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

प्रदेश को निर्धारित समयावधि में खुले में शौचमुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित सामग्री का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाए।